

Public Debt and its types

सार्वजनिक ऋण एवं इसके प्रकार

वर्तमान समय में लोककल्याणकारी राज्यों के विकास के कारण सरकारी व्ययों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी है जिस पूरा करने के लिए सरकार धाटे की वित्त व्यवस्था बनाती है। लेकिन इन व्ययों की पूर्ति जब सरकारी आय से नहीं होता तो सरकार को ऋण लेना पड़ता है जिस सार्वजनिक ऋण कहते हैं।

सार्वजनिक ऋण की विभिन्न किस्में निम्नलिखित हैं -

1. आन्तरिक एवं बाह्य ऋण (Internal and External Debt)

आन्तरिक ऋण तो ऋण होते हैं जो देश के ~~भीतर~~ अन्दर देश के नागरिकों, बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त किये जाते हैं।

जबकि बाह्य ऋण विदेशी सरकारों, विदेशी व्यक्तियों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त किये जाते हैं।

2. उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण - (Productive and Un-productive Debt)

उत्पादक ऋण उन ऋणों को कहते हैं - जिनका उपयोग ऐसी परियोजनाओं में किया जाता है जिसे आय प्राप्त होती है जैसे कि रेलवे, बिजली, सिंचाई की योजनाएँ।

अनुत्पादक ऋण उन ऋणों को कहते हैं जो ऐसी परियोजनाओं में लगाये जाते हैं - जिनसे आय प्राप्त नहीं होती जैसे युद्ध, बाढ़, वैराजगारी गन्ता, श्रृंखला घन्ना आदि।

3. शोध्य तथा अशोध्य ऋण (Redeemable and Irredeemable Debt)

शोध्य ऋण उन ऋणों को कहते हैं जिनके बारे में सरकार यह वाचता करती है कि वह उन्हें एक निश्चित तिथि पर लाज सहित अदा करेगी। शोध्य ऋणों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अल्पकालीन ऋण 3 से 9 माह की अवधि के बीच परिपक्व हो जाते हैं जैसे - राजकोष पत्र (Treasury bills) मध्यकालीन ऋण पांच वर्ष बाद परिपक्व होते हैं और दीर्घकालीन ऋण 10 से 15 वर्षों के बीच होती हैं। इसपर लाज दर कुची होती है। अशोध्य ऋण वह होते हैं जिसे सरकार लेती है किन्तु वापस करने का कोई वादा नहीं करती है। अशोध्य ऋण सार्वजनिक ऋण पर सरकार निश्चित रूप से लाज अदा करती है किन्तु मूलधन वापस नहीं करती इसलिए Irredeemable Public debt को Perpetual Public debt भी कहा जाता है।

4. निधिजन्य तथा अनिधिजन्य ऋण (Funded and unfunded Debt)

निधिजन्य ऋण दीर्घकालीन ऋण होते हैं। इन ऋणों की अदायगी या तो कत से कत एक वर्ष बाद की जा सकती है अथवा यह भी हो सकता है कि इस सम्बन्ध में बिल्कुल ही वापदा न किया जाय। जबकि अनिधिजन्य ऋण वे ऋण

होता है - जिसका मुद्दा एक वर्ष के अन्दर कर दिया जाता है। राजकाशी बॉन्ड (Treasury bonds) अधिकतम ऋण होता है जोकि 30 दिन या 90 दिनों के लिए दिए जाते हैं।

5. ऐच्छिक और अनिवार्य ऋण (Voluntary and Compulsory Debt)

सरकारी ऋण सामान्यतः ऐच्छिक प्रकृति के होते हैं। ~~जोकि~~ बिना किसी दबाव के या बिना किसी प्रयत्न के जो ऋण सरकार को मिल जाते हैं उन्हें ऐच्छिक ऋण कहा जाता है।

जबकि अनिवार्य ऋण दबाव से वसूल किए जाते हैं। जब सरकार को ऋणों की आवश्यकता होती है और उसे आसानी से ऋण प्राप्त नहीं होता तो सरकार दबाव डालकर ऋण वसूल करने का प्रयत्न करती है। सरकार ऐसा ही करती है जब उसके सामने राष्ट्रीय संकट होता है। आमतौर पर अनिवार्य सार्वजनिक ऋण पर आज तुलनात्मक रूप में अधिक रकम है इसलिए ऐच्छिक सार्वजनिक ऋण कमलता सरल होता है।

6. धाज सहित और धाज रहित ऋण (With Interest and Without Interest debt)

धाज सहित ऋणों पर सरकार निश्चित अवधि के पश्चात्, ऋणदाताओं की निश्चित अवधि के पश्चात्, ऋणदाताओं की निश्चित दर से धाज देती है जबकि ~~रुख~~ धाजरहित ऋणों पर सरकार को कोई ~~रुख~~

भाज नहीं देना पड़ता। आज कोई भी सरकार बिना भाज से उठाने नहीं लेती है प्राचीन काल में शासकों के द्वारा बिना भाज का उठाने लिया जाता था।

7. क्रय योग्य व अक्रय योग्य ऋण
(Perchusable and Non-Perchusable Debt)

क्रय योग्य ऋण व- ऋण हैं जिनमें ऋण पत्र खुले बाजार में खरीदे व बेचे जाते हैं जैसे - सरकारी प्रतिभूतियाँ।

अक्रय योग्य ऋण व- होते हैं जिन्हें खुले बाजार में खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है परन्तु पुनर्विचारित इतरे पर केवल सरकार के हाथ ही बेचा जा सकता है जैसे - डाकखाने का बचत ऋण पत्र।

8. कुल ऋण एवं शुद्ध ऋण
(Total debt and Net debt)

कुल ऋण विषय पर सरकार के गिर्तन किये गये हैं उन सबके योग को कुल ऋण कहा जाता है।

कुल ऋण में से ऋणवोपन के लिए कोष में जमा की गयी राशि को बटा देने के बाद जो शेष बचता है- उसे शुद्ध ऋण कहा जाता है।

9. अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण
(Short term and Long term Debt)

जब सरकार अल्प काल के लिए ऋण लेती है तो उसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं। इन ऋणों को एक वर्ष की अवधि में वापस कर दिया जाता है।

जब सरकार कहीं काले अपने समय के लिए
नियम लेती है उसी शीर्षकालीन नियम कहते हैं।
इन्हीं लॉयर्स को कोई समय निश्चित नहीं
होता है लेकिन जब तक नियम का अंगुतान नहीं
किया जाता तब तक नियमावली का अंगुतान मिलता
रहता है।

इस प्रकार I.K. Mehta का कहना
है कि "सार्वजनिक नियम एक दूसरे से
मिलते हैं और क्योंकि उनका आधार अलग
अलग होता है। इनमें एक अन्तर बाजार,
अंगुतान, नियम चुकाने के अंगुतान, आदि के
कारण होता है।"

—————X—————

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College